RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 17 JUNE TO 23 JUNE 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 43 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

व्यापारियों के संगठन CAIT ने किया चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान Page 2

जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न का ब्याज कम किया Page 3

30 जून तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो बढ़ जाएगी परेशानी Page 4

editoria!

देश में मंदी का दौर

कोरोना और लॉकडाउन ने हमें कितने गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है, दुनिया अब धीरे-धीरे इसका हिसाब लगाने की स्थिति में पहुंच रही है। विश्व बैंक ने पिछले दिनों अपनी ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि महामारी और शटडाउन के सम्मिलित प्रभावों से इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.2 फीसदी तक सिकुड़ सकती है। इसे दूसरे शब्दो में यूं कहा गया है कि दुनिया दूसरे विश्वयुद्ध के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक संसार की 90 फीसदी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की यह लहर 1930 की ऐतिहासिक मंदी से भी ज्यादा तेज होगी। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों और राहतों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में 3.2 फीसदी सिकुड़ सकती है। अभी अप्रैल में विश्व बैंक ने उम्मीद जताई थी कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस साल 1.5 से 2.8 फीसदी तक की ग्रोथ हो सकती है। जाहिर है, कोरोना वायरस सबके अनुमान से कहीं ज्यादा मारक साबित हुआ है, और अभी इसके काबू में आने की शुरुआत भी नहीं हुई है। ऐसा मानने की कोई गुंजाइश नहीं है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जरूरत से ज्यादा निराशाजनक तस्वीर पेश कर रही है। गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा जैसी अन्य वित्तीय एजेंसियां तो मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 फीसदी तक की सिकुड़न आने की बात कह रही हैं। बहरहाल, आंकड़ों से अलग हटकर समझने की कोशिश करें तो स्थिति यह है कि सरकारी क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को छोड़कर इकॉनमी के हर सेक्टर में मंदी के भीषण प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इन क्षेत्रों में कई कंपनियां बंद होंगी और लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार होंगे। सरकार के साधन भी सीमित हैं इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इन सीमित संसाधनों का इस्तेमाल सोच-समझ कर किया जाए। विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारी कोशिश अर्थव्यवस्था में नीचे से मांग पैदा करने की होनी चाहिए। यह तभी होगा जब सबसे ज्यादा चिंता लोगों के रोजगार की ही की जाएगी। यानी यह एक महत्वपूर्ण सूत्र हो सकता है कि सरकार उन क्षेत्रों की मदद को प्राथमिकता दे जो सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराते हैं। दूसरी बड़ी जरूरत महत्वपूर्ण आंकड़ों की कमी को तत्काल दूर करने की है। देश में खपत के ट्रेंड बताने वाले कंजंप्शन-एक्सपेंडिचर सर्वे (सीईएस) 2011-12 के बाद से करवाए ही नहीं गए हैं। तिमाही आधार पर रोजगार और बेरोजगारी बताने वाले आंकड़े जुटाए तो जा रहे हैं, लेकिन नियमित तौर पर जारी नहीं किए जा रहे। 2018-19 के आंकडे इस महीने जारी हुए हैं। इस धुंध से सटीक फैसले करने में दिक्कत होगी। यह ऐसा वक्त है जब हमें बुरी खबरों से डरने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। हम बुरे हाल में हैं, सबको पता है।

तेल रिफाइनिंग क्षमता 2030 तक दोगुना करने की योजना : प्रधान

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि देश में तेल शोधन क्षमता को दस साल में दोगुना कर 45 से 50 करोड़ टन तक पहुंचाने की योजना है। घरेलू मांग को पूरा करने के साथ साथ पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात मांग को पूरा करने के लिये यह योजना बनाई गई है। प्रधान ने 'आत्मनिर्भर भारतः तेल एवं गैस क्षेत्र में घरेलू इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने' पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुये कहा कि शोधन क्षमता को दोगुना करने के मामले में काफी अहम भूमिका निभाने वाली छह करोड़ टन सालाना क्षमता की पश्चिमी तट रिफाइनरी का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा, "हमारी तेल शोधन क्षमता करीब 25 करोड़ टन से बढ़कर अगले दस साल के दौरान 45 से 50 करोड़ टन सालाना तक पहुंच जायेगी।" उन्होंने कहा, "शोधन क्षमता में यह वृद्धि दोनों तरह से हासिल की जायेगा। मौजूदा रिफाइनरियों का विस्तार करने के साथ ही नई रिफाइनरी लगाई जायेगी।

वर्तमान में 21.37 करोड़ टन ईंधन की मांग के मुकाबले तेल शोधन क्षमता बढ़कर 24.99 करोड़ टन तक पहुंची है लेकिन 2030 तक देश में ईंधन की मांग बढ़कर 33.50 करोड़ टन

और 2040 तक 47.20 करोड़ टन तक पहुंच जाने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अनुमान व्यक्ति किया है कि 2040 तक भारत की ऊर्जा मांग 45.80 करोड़ टन सालाना तक पहुंच जायेगी। भारत दुनिया का तीसरा बड़ तेल उपभोक्ता है। भारत अपनी कुल जरूरत का 85 प्रतिशत तक आयात करता है। वह आने वाले समय के लिये बढ़ती मांग को पूरा करने की योजना तैयार कर रहा है। प्रधान ने कहा कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये कदम उठा रहा है।

राजस्थान के बाड़मेर में 90 लाख टन शोधन क्षमता की नई रिफाइनरी लगाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य जारी है वहीं गुजरात की कोयली, हरियाणा में पानीपत, ओडिशा में पारादीप, आंध्र प्रदेश में विजाग, मुंबई, मध्यप्रदेश के बीना, असम के नुमाली गढ़ और तमिलनाडू में चेन्नई स्थित मौजूदा रिफाइनरियों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "पश्चिम तटीय रिफाइनरी का निर्माण जल्द शुरू किया जायेगा।" उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के निर्माण के साथ साथ तेल एवं गैस की पाइपलाइन बिछाने और शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार कार्यों में इस्पात की मांग बढ़ेगी।

इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) के चेयरमैन संजीव सिंह ने वेबिनार में रिफाइनिंग क्षमता के विस्तार पर गठित कार्य समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुये कहा कि भारत की रिफाइनिंग क्षमता 2030 तक बढ़कर 36.30 करोड़ टन, 2035 तक 44.30 करोड़ टन और 2040 तक बढ़कर 53.30 करोड़ टन सालाना तक पहुंच जायेगी। इसके साथ ही भारत की एलएनजी आयात क्षमता 2030 तक चार करोड़ टन बढ़ेगी। वर्तमान में देश की एलएनजी आयात क्षमता 4.25 करोड़ टन है।

संजीव सिंह ने कहा कि हाल के महीनों में हालांकि ईंधन की मांग तेजी से कम हुई है। देश में जारी लॉकडाउन के कारण इसमें कमी आई, लेकिन दो साल की अवधि में "हम फिर से प्रस्तावित मांग के दायरे में पहुंच जायेंगे।" उन्होंने कहा कि तेल एवं गैस क्षेत्र में विस्तार की योजना काफी व्यापक है। आने वाले समय में मौजूदा 69,109 पेट्रोल पंप के ऊपर 78,000 नये पेट्रोल पंप खोले जायेंगे। इसके साथ ही सीएनजी पंपों की संख्या भी 2,207 बढ़ाकर 10,000 तक पहुंच जायेगी। पाइपलाइन नेटवर्क में भी 15,000 किलोमीअर का विस्तार कर इसे 43,000 किलोमीटर तक पहुंचा दिया जायेगा इसी प्रकार प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन में भी 14,239 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

तेल की खपत में 85 फीसदी की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अनलॉक 1.0 के शुरू होने के साथ ही तेल की खपत में भी 85 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि पूरी तरह से ग्रोथ होने में अभी कम से कम दो साल का वक्त और लगेगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। वहीं उद्योग ने कहा कि ईंधन मांग में 5 फीसदी वृद्धि आने में दो साल लग सकता है। इसी कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा कि ईंधन के मामले में 4-5 प्रतिशत वृद्धि के रास्ते पर लौटने में 2 साल का समय लगेगा। वित्त वर्ष 2019-20 में धीमी आर्थिक गतिविधियों कारण ईंधन की बिक्री हल्की हुई थी। उससे पहले मांग में 4 से 5 फीसदी की वृद्धि हो रही थी. मई में ईंधन खपत 1.465 करोड़ टन रही जो अप्रैल के मुकाबले 47.4 फीसदी अधिक है। लेकिन एक साल पहले की तुलना में 23.3 प्रतिशत कम है। सर्वाधिक खपत वाला ईंधन डीजल की मांग मई में करीब 29.4 फीसदी कम हुई जबकि पेट्रोल की बिक्री 35.3 प्रतिशत घटी है। उद्योग के आंकड़े के अनुसार 1 जून से 15 जून के दौरान डीजल मांग में सुधार आया और यह 26.7 लाख टन रहा जो एक साल पहले इसी अवधि के मुकाबले 15 फीसदी कम है। वहीं पेट्रोल की बिक्री इसी अवधि 9,30,000 टन रही जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 18 फीसदी कम है।

Unlock 1.0 का असर

डब्ल्यूईएफ की 2020 के तकनीकी दिग्गजों की सूची में दो भारतीय कंपनियां शामिल

नयी दिल्ली। एजेंसी

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा मंगलवार को जारी 2020 के तकनीकी दिग्गजों की सूची में दो भारतीय कंपनियों - जेस्टमनी और स्टेलाएप्स को शामिल किया है। इस सूची में कुल 100 कंपनियों के नाम हैं, जिनके बारे में डब्ल्यूईएफ ने कहा कि भविष्य में इनका बड़ा नाम होगा और ये बेहतरीन प्रौद्योगिकी के जरिए वैश्विक समस्याओं का समाधान मुहैया कराएंगी। जेस्टमनी के बारे में डब्ल्यूईएफ ने कहा कि कंपनी अपनी तकनीक का इस्तेमाल वित्तीय सेवा उद्योग की तस्वीर बदलने के लिए कर रही है, जिसके जरिए लोगों को सस्ते कर्ज की पेशकश की जा रही है। कंपनी किफायती ऋण देने के लिए कृत्रिम मेधा आधारित डिजिटल लैंडिंग प्लेटफार्म का इस्तेमाल करती है और उन लोगों को कर्ज देती है, जिनकी आमतौर पर पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच नहीं है। सूची में शामिल एक अन्य भारतीय कंपनी स्टेलाएप्स डाटा आधारित इंटरनेट सेवा है, जो किसान से उपभोक्ता तक डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटलीकरण का काम करती है।

लगातार 11वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम कच्चा तेल नरम

नई दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोल और डीजल की महंगाई का सिलसिला बुधवार को 11वें दिन जारी रहा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में नरमी बनी रही। लगातार 11 दिनों की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 6.02 रुपए प्रति

लीटर महंगा हो गया है और डीजल की कीमत 6.42 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतों में क्रमशः 55 पैसे 53 पैसे, 53 पैसे, 49 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। वहीं, डीजल के दाम में चारों महानगरों में क्रमशः 60 पैसे, 54 पैसे, 57 पैसे और 52 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर क्रमशः 77.28 रुपये, 79.08 रुपये, 84.15 रुपये और 80.86 रुपये प्रति लीटर हो गई। डीजल का दाम भी चारों महानगरों में बढ़कर क्रमशः 75.79 रुपये, 71.38 रुपये, 74.32 रुपये और 73.69 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज यानी आईसीई पर बुधवार को अगस्त डिलीवरी ब्रेंट क्रूड के वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 1.12 फीसदी की कमजोरी के साथ 40.50 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी नायमैक्स पर अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई के जुलाई डिलीवरी अनुबंध पिछले सत्र से 1.69 फीसदी की नरमी के साथ 37.73 डॉलर प्रति बैरल पर कोराबार चल रहा था।

व्यापारियों के संगठन CAIT ने किया चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान

500 से अधिक वस्तुओं की सूची की जारी

नई दिल्ली। एजेंसी

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा करते हुए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया है। कैट ने करीब 500 आयातित वस्तुओं की सूची भी तैयार की है। सीएआईटी ने कहा कि उसका उद्देश्य दिसंबर 2021 तक चीनी तैयार माल के आयात को 13 बिलियन डॉलर या लगभग 1 लाख करोड़ रुपये कम करना है। सोमवार को लद्दाख में गलवान घाटी के पास भारत-चीन के बीच हुए टकराव के बाद कैट ने यह कदम उठाया है। कैट द्वारा तैयार की गई इस सूची में रोज़मर्रा में काम आने वाली वस्तुएं जैसे- खिलौने, फर्निशिंग फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर हार्डवेयर, फुटवियर, गारमेंट, किचन का सामान, लगेज, हैंड बैग,खाद्यान,घड़ियाँ, जैम एंड ज्वेलरी, वस्त्र, स्टेशनरी, कागज़, घरेलू वस्तुएं,फर्नीचर,लाइटिंग, हेल्थ प्रोडक्ट्स,पैकेजिंग प्रोडक्ट,ऑटो पार्ट्स, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन अपैरल, यार्न, फेंगशुई आइटम्स, दिवाली एवं होली का सामान, चश्में,टेपेस्ट्री मैटेरियल आदि शामिल हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस अभियान के बारे में कहा, 'चीन से भारत का आयात लगभग 5.25 लाख करोड़ अर्थात 70 बिलियन डॉलर सालाना है। कैट ने प्रारंभिक चरण में 3,000 से अधिक उत्पादों का चयन किया है, जो भारत में भी बनती हैं, लेकिन कम कीमत के लालच में चीन से इन वस्तुओं को आयात किया जा रहा है। इन चीनी वस्तुओं के स्थान पर भारत में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग काफी सहजता से किया जा सकता है।' उन्होंने आगे कहा, 'जिन उत्पादों में तकनीक महत्व है, अभी उनको बहिष्कार में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक इस प्रकार की तकनीक का विकल्प भारत में विकसित नहीं हो जाता या भारत के किसी मित्र देश द्वारा वह उत्पाद निर्मित नहीं होता, तब तक उस प्रकार की तकनीक वाली वस्तुओं के उपयोग के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।'

लॉकडाउन: घर में बैठे-बैठे हर भारतीय ने औसतन 2 घंटे अधिक इस्तेमाल किया मोबाइल-लैपटॉप

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले दिनों कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन था। इस दौरान लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट भी खूब हुआ और स्ट्रीमिंग भी खूब हुई। इस पूरे वक्त में लोगों का स्क्रीन टाइम पहले की तुलना में करीब दोगुना हो गया है। लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में थे, ऐसे में डिजिटल और इंटरनेट देश की रीढ़ बन गए, जिसकी चलते ऑनलाइन खपत में करीब 20 फीसदी का इजाफा हुआ है। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन का इस्तेमाल जहां पहले प्रति व्यक्ति औसतन 3 घंटे होता था, वो 5 घंटे तक चला गया। ब्रॉडबैंड या वाईफाई से जुड़े रहने के दौरान पहले औसतन एक व्यक्ति 2.5 घंटे स्क्रीन इस्तेमाल करता था, अब वह आंकड़ा 4.5 घंटे तक जा पहुंचा है। दुनिया भर में 2019 में भारत में सबसे अधिक इंटरनेट इस्तेमाल किया गया था, जो इस बार लॉकडाउन में और बढ़ गया है। 20199 में भारत में प्रति यूजर हर महीने करीब 12 जीबी डेटा इस्तेमाल किया गया, जबकि ग्लोबल एवरेज महज 7 जीबी था। माना जा रहा है कि अगले 5 सालों में ये आंकड़ा 25 जीबी तक पहुंच सकता है।

भारत हुआ अनलॉक तो तेजी से घटी बेरोजगारी दर 14 जून तक 11.63% पर आई

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना महामारी के कारण 25 मार्च से 31 मई तक चले लॉकडाउन के बाद भारत जैसे ही अनलॉक हुआ जून के दूसरे सप्ताह में आश्चर्यजनक रूप से बेरोजगारी दर में कमी आ गई। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 14 जून को समाप्त सप्ताह में 11.63% तक तेजी से गिर गई। यह आंकड़ा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा एक सर्वेक्षण से मिला है।

22 मार्च को देश मे बेरोजगारी दर 8.41 फीसद थी, जो कोरोना महमारी के चलते लॉकडाउन में 5 अप्रैल को बढ़कर 23.38 फीसद हो गई। वहीं 11 मई को यह 24.0 फीसद पर पहुंच गई। अब जब लॉकडाउन में बहुत सारी ढील दे दी गई तो यह घटकर 11.63 पर आ गई है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 22 मार्च को बेरोजगारी दर 8.66 फीसद थी जो 5 अप्रैल को बढ़कर 30.93 फीसद पर पहुंच गई थी। वहीं यह 17 मई को 26.95 फीसद थी। जबकि, 14 जून को यह गिरकर 13.10 रह गई है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 22 मार्च को यह 8.29 फीसद थी 5 अप्रैल तक आते-आते 20.21 पर पहुंच गई। लॉकडाउन का असर शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में असर थोड़ा कम रहा और 17 मई को बेरोजगारी दर 22.79 फीसद पर पहुंच गई, जबकि इसी दौरान शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 26.95 फीसद थी। अब 14 जून को यह गिरकर 10.96 फीसद पर आ गई है।

इस मामले में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरूप मित्रा कहते हैं, 'जो लोग पहले मजदूरी करते थे, वे अब गाँवों में चले गए हैं और अब या तो आकस्मिक काम या कृषि-कार्य में हैं। मासिक वेतन या ऑफिस सपोर्ट स्टाफ वाले ड्राइवर जो नौकरी छूटने और वेतन की हानि के कारण वापस चले गए हैं, वे रोजगार वालों के रूप में गिने तो जाएंगे पर तकनीकी रूप से उन्हें नियोजित कहा जाएगा।

अभी से लेकर 2050 तक ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 55 डॉलर प्रति बैरल रह सकती है : ब्रिटिश पेट्रोलियम

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्रिटेन की पेट्रोलियम कंपनी ब्रिटश पेट्रोलियम (बीपी) ने अनुमान जताया है कि आने वाले कई दशकों में तेल की कीमत कम रहेगी। कंपनी ने कहा है कि कोरोनावायरस महामारी के बाद दुनियाभर की सरकारें कार्बन उत्सर्जन घटाने की कोशिश तेज करेंगी, इसलिए तेल की कीमत कम रहेगी। कंपनी ने तेल मूल्य के अनुमान में कटौती की है और कहा है कि अभी से लेकर 2050 तक ब्रेंट क्रूड की कीमत औसतन 55 डॉलर प्रति बैरल रह सकती है।

संपत्तियों की कीमत 17.5 अरब डॉलर तक घटाएगी बीपी

एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि तेल मूल्य में गिरावट के अनुमान के कारण वह अपनी संपत्तियों के मूल्य को 13-17.5 अरब डॉलर घटाएगी। बीपी ने कहा कि उसे छोटी, तेज और कम लागत वाली कंपनी बनना होगा। हाल में दुनियाभर

में तेल की कीमत में भारी गिरावट देखे जाने के बाद पिछले सप्ताह कंपनी ने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के फैसले की घोषणा की थी।

दुनियाभर में लॉकडाउन के कारण घट गई है तेल की मांग

कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए दुनियाभर की सरकारों ने अपने नागरिकों को घर में रहने और यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। इससे दुनियाभर में तेल की मांग घट गई है। इसके कारण पिछले दिनों तेल की कीमत घटकर 20 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई थी, जो इस साल की शुरुआत में दर्ज की गई करीब 66 डॉलर के मूल्य के मुकाबले एक तिहाई से भी कम है।

हाल में तेल कंपनियों को डिलीवरी लेने के लिए खरीदारों को पैसे भी देने पड़े थे

एक समय तो ऐसा भी आया जब तेल रखने के लिए भंडारण सुविधा कम पड़ गई और कंपनियों को तेल खरीदारों को डिलीवरी लेने के लिए पैसे भी देने पड़े। इसके बाद से अब तक कीमत में कुछ सुधार आया है। फिलहाल क्रूड ऑयल करीब 37 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है।

पर्यावरण बचाना है तो तेल का उपयोग घटाना होगा

बीबीसी के पर्यावरण विश्लेषक रोजर हैराबिन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ कई साल से चेतावनी दे रहे हैं कि यदि पर्यावरण को बचाना है, तो कंपनियां जितने तेल की खोज कर चुकी हैं, उतने का उपयोग नहीं किया जा सकता। हमें देखना होगा कि बीपी के नजरिए के बारे में अन्य कंपनियों का क्या कहना है।

बीपी कुछ तेल फील्ड के विकास की योजना को ठंडे बस्ते में डाल सकती है

ब्रिटिश कंपनी के ताजा बयान का मतलब यह है कि कंपनी जितने तेल को जमीन से निकालने की योजना पर काम कर रही है, उसकी कीमत पहले जताए गए अनुमान से कम है। ऐसी संभावना है कि कंपनी कुछ तेल फील्ड का विकास भी न करे। अब देखना यह है कि क्या अन्य वैश्विक तेल कंपनियां भी बीपी की राह पर चलेंगी।

टैक्स की सुविधा

जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न का ब्याज कम किया

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

ऐसे व्यापारी जिन्होंने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के जीएसटी रिटर्न फाइनल नहीं किए हैं और इन पर कोई टैक्स बकाया नहीं है तो ऐसे व्यापारियों को अब रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस नहीं भरना होगी। छोटे व्यापारियों को भी 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने का समय दिया गया है।

निर्धारित समय के बाद ब्याज की दरों को 50 प्रतिशत तक कम किया गया है जिससे छोटे-बड़े व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जानकारों ने बताया कि 5 करोड़ से कम टर्न ओवर वालों को भी फायदा हो रहा है। इसके चलते फरवरी 2020 से मई 2020 तक जो रिटर्न फाइल किए जाएंगे। उसमें 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। अगर 1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 20 तक अगर कोई व्यवसायिक टर्न ओवर नहीं हुआ है तो इस अवधि की उन्हें लेट फीस नहीं देना होगी। यदि व्यापारी की किसी महीने में टैक्स की देनदारी होती है, तो उसे पूर्व में अधिकतम 10 हजार रुपए टैक्स लगता था जो कि अब 500 रुपए प्रतिमाह तक सीमित कर दिया गया है। 5 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों को फरवरी, मार्च का रिटर्न 30 जून, अप्रैल का रिटर्न 6 जुलाई तक और मई

का 13 जुलाई तक भरना होगा।

व्यापारियों को यह लाभ: छोटे व्यवसायियों को फरवरी से अप्रैल 2020 का जीएसटी रिटर्न 6 जुलाई 2020 तक भरने पर कोई लेट फीस और ब्याज नहीं लगेगा। 6 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर 30 सितंबर 2020 तक जीएसटी रिटर्न जमा करने पर केवल 9% ब्याज देना होगा।

ये भी मिली सुविधा: ऐसे करदाता जिनका पंजीयन 12 जून 2020 के पहले रिटर्न नहीं भरने के कारण निरस्त हो गया था। उन्हें सरकार द्वारा एक मौका दिया गया है, अगर वे 1 जुलाई 2017 से 30 जनवरी 2020 तक का रिटर्न 1 जुलाई 20 से 30 जून 20 तक जमा कर देते हैं तो उनके निरस्त पंजीयन चालू हो जाएंगे।

5 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के लिए

5 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारी अगर फरवरी, मार्च और अप्रैल का रिटर्न 20 मई तक भर देते हैं तो उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर वे इसके बाद रिटर्न भरते हैं तो 24 जून तक 18 प्रतिशत की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना पड़ेगा। व्यापारियों को 24 जून तक फरवरी, मार्च और अप्रैल के सारे रिटर्न भरने हैं। जिन व्यापारियों ने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का जीएसटी रिटर्न तीन बी फाइल नहीं किया है तो प्रति 500 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से लेट फीस लागू होगी। घटी दर की लेट फीस 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के दौरान जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर लागू होगी।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे मजबूत होकर 76.16 पर बंद

मुंबई। एजेंसी

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुरूआती गिरावट से उबरते हुए अंत में 4 पैसे की मजबूती के साथ 76.16 रुपये प्रति डालर के अस्थाई भाव पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में तेजी और दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के कमजोर होने से रुपये पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।हालांकि, विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार चीन के साथ सीमा विवाद, विदेशी पूंजी निकासी और कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हो रही है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया गिरावट के साथ खुला लेकिन बाद में इसमें तेजी आयी और अंत में यह 4 पैसे बढ़त के साथ 76.16 पर बंद हुआ। रुपया मंगलार को 76.20 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान रुपया ऊंचे में 76.10 और नीचे में 76.25 रुपये प्रति डालर तक गया।

7600 करोड़ रु. या उससे ज्यादा वैल्यू वाले

भारत के 30 में से 18 स्टार्टअप में चीन की हिस्सेदारी

बायजूस, ओला, पेटीएम और जोमैटो में बड़ा निवेश

नई दिल्ली। एजेंसी

लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सरहदी विवाद अब तक के सबसे खराब हाल में है। दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने है। वहीं, पिछले पांच-छह सालों में चीन के भारतीय कंपनियों में पैसा लगाने की रफ्तार लगातार बढ़ती रही है। इससे भारतीय बाजार में उसकी पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत होने के आसार हैं। तनाव बढ़ने से दोनों देशों को नुकसान होगा, लेकिन भारत पर अधिक असर पड़ सकता है। चीन की कई बड़ी कंपनियों ने भारत में निवेश बढ़ाया है। भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न, यानी एक अरब डॉलर (करीब 7600 करोड़ रुपए) या उससे अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनी में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है।

पिछले 7 साल के दौरान सबसे ज्यादा 1666 मिलियन डॉलर का निवेश 2017 में हुआ

रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनियों ने 2014 में भारत की कंपनियों में 51 मिलियन डॉलर निवेश किया था। यह 2019 में बढ़कर 1230 मिलियन डॉलर हो गया यानी 2014 से 2019 के बीच चीन ने भारतीय स्टार्टअप्स में कुल 5.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। चीन की जिन कपंनियों ने भारत में निवेश किया उनमें अलीबाबा, टेंशेट और टीआर कैपिटल सहित कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं।

भारत की 30 यूनिकॉर्न में से 18 में चीन की हिस्सेदारी

मुंबई के विदेशी मामलों के थिंक टैंक 'गेटवे हाउस' ने भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की है जो ई-कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया/सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विस और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं में हैं और उनमें चीन का निवेश है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन एक अरब डॉलर या उससे अधिक होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी क्षेत्र में ज्यादा निवेश के कारण चीन ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया है।

सितंबर-अक्तूबर में अंतिम राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है सरकार: RBI निदेशक

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशक एस गुरुमूर्ति ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 संकट के बाद सितंबर में अंतिम राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। गुरुमूर्ति ने भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के पैकेज को अंतरिम उपाय माना जा सकता है।

घाटे को भरने के लिए मुद्रा की छपाई कर रहा अमेरिका

आरएसएस विचारक ने कहा कि, 'अंतिम प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कोविड संकट के बाद सितंबर में या अक्तूबर में होने की उम्मीद है। यूरोपीय देश और अमेरिका घाटे को भरने के लिए मुद्रा की छपाई कर रहे हैं, जबकि भारत के लिए ऐसा करने की बहुत कम गुंजाइश है।'

अभी तक मौद्रीकरण के विकल्प पर विचार नहीं

गुरुमूर्ति ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने अभी तक घाटे के मौद्रीकरण (नोट छापने) के विकल्प पर कोई विचार नहीं किया है। घाटे के मौद्रीकरण के तहत केंद्रीय बैंक सरकार की खर्च जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी बॉन्ड खरीदा है और बदले में अपनी निधि से या नए नोट छापकर सरकार को धनराशि देता है।

तेजी से वापसी करेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

उन्होंने कहा, 'भारत कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार ने एक अप्रैल से 15 मई तक जन-धन बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं। आश्चर्य की बात है कि उन खातों से बहुत कम धन निकाला गया है। इससे पता चलता है कि संकट का स्तर उतना अधिक नहीं है।' उन्होंने कहा कि कोविड संकट के बाद के युग में दुनिया 'बहुपक्षीयवाद से द्विपक्षीयवाद' में बदल जाएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से वापसी करेगी।

20 लाख 97 हजार 53 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज

मालूम हो कि सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार ने अब तक 20 लाख 97 हजार 53 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार पांच दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्थव्यवस्था के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण कदमों की विस्तार से जानकारी दी थी। सरकार ने समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा किया है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने किसान, प्रवासी मजदूर, कॉर्पोरेट सेक्टर, आदि के लिए हर जरूरी कदम उठाया है।

30 जून तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो बढ़ जाएगी परेशानी

कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार द्वारा किए गए देशव्यापी लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई है। भले ही लॉकडाउन का खुलना शुरू हो गया है, इसी बीच सरकार ने भी कई चीजों की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है, ताकि आम लोगों को घर से बहार नहीं निकलना पड़े। हम आपको इनकम टैक्स और इंश्योरेंस सहित कुल 10 कामों के लिए डेडलाइन 30 जून रखी गई है। आइए, इनसे एक-एक कर रूबरू होते हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश

सरकार फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा चुकी है। योजना के नियमों के मुताबिक, 55-60 साल आयु के रिटायर लोग एससीएसएस स्कीम में सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भीतर निवेश कर सकते हैं।

आधार-पैन लिंकिंग

सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। पहले यह 31 मार्च थी। अब अगर 30 जून डेडलाइन के अंदर आधार के साथ पैन लिंक नहीं किया गया तो यह मान्य नहीं रह जाएगा।

PPF, SSY का न्यूनतम अमाउंट

सरकार ने PPF और सुकन्या समृद्धि (SSY) अकाउंटहोल्डर्स को राहत दी और दोनों अकाउंट के प्रावधानों में ढील देते हुए फैसला किया कि जो लोग PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लॉकडाउन के चलते वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मिनिमम डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं, वे अब 30 जून 2020 तक ऐसा कर सकते हैं।

अडवांस टैक्स

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स के भुगतान की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। इसलिए जो टैक्सपेयर्स अडवांस टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं, उन्हें सुझाव है कि वे 30 जून से पहले टैक्स जमा कर दें, जिससे टैक्स लायबिलिटी पर कोई ब्याज न हो।

ऑटो डेबिट फैसिलिटी

पेंशन फंड रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अटल पेंशन योजना (APY) के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी को 30 जून 2020 तक के लिए रोक दिया है। यानी जो लोग APY में निवेश कर रहे हैं, उनके सेविंग्स अकाउंट से अपने आप इस स्कीम के लिए योगदान का पैसा नहीं कटेगा।

मिनिमम बैलेंस में छूट

सरकार ने 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को भी खत्म किया हुआ है। अगर ग्राहक के बचत खाते में मिनिमम बैलेंस मौजूद नहीं हुआ तो बैंक उससे चार्ज नहीं वसूलेंगे।

लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम

पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भुगतान पीरियड को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। सभी PLI और RPLI पॉलिसी धारकों को राहत देने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, संचार मंत्रालय ने मार्च 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020 के बकाया प्रीमियम के भुगतान की अवधि को 30 जून 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया।

फॉर्म 15G/15H जमा करें

सरकार ने जमा किए जा चुके फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया है। CBDT ने तय किया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में जमा किए गए फॉर्म 15उ/15ए 30 जून 2020 तक मान्य रहेंगे और बैंक/फाइनैंशल इंस्टीट्यूशन निवेशकों की ब्याज आय पर जून आखिर तक टैक्स नहीं काटेंगे।

PPF अकाउंट एक्सटेंड की डेडलाइन बढ़ी

जिन लोगों का PPF अकाउंट 31 मार्च को मैच्योर हुआ है, जिसमें एक साल का एक्सटेंशन भी शामिल है, वे लोग अगर अपने PPF अकाउंट को आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसा मार्च 2020 तक नहीं कर पाए हैं, तो उनके पास अकाउंट एक्सटेंड कराने के लिए फॉर्म जमा करने का मौका 30 जून 2020 तक रहेगा।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)

अब करदाताओं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेट ITR 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर पहले आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो उसमें करेक्शन करने का यानी रिवाइज ITR भरने का भी मौका मिलेगा।

कोरोना वायरस ने तोड़ी अर्थव्यवस्था की कमर

ये संपन्न देश भी बेहाल, लाखों लोगों की गईं नौकरियां

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के चलते श्रम बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या छह लाख से अधिक कम हो गई है। समाचार एजेंसी के अनुसार, ओएनएस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मई के शुरुआती संकेतक बताते हैं कि ब्रिटेन में पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या में मार्च की तुलना में 2.1 प्रतिशत या 612,000 की गिरावट हुई है।

ओएनएस डेटा से पता चलता है कि मार्च से मई तक पूरे ब्रिटेन में 476,000 रिक्तियां थीं, जो पिछली तिमाही (दिसंबर 2019 से फरवरी 2020) से 342,000 कम है। यह 2001 में शुरू हुई मौजूदा सीरीज के बाद से अबतक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट है। आंकड़े के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों के कारण होटल, रेस्टॉरेंट और खुदरा स्टोर बंद होने के चलते थोक, खुदरा कारोबार और मोटर वाहन रिपेयर औद्योगिक सेक्टर में रिक्तियों में 49.9 प्रतिशत तिमाही गिरावट आई है और एकोमोडेशन और फूड सर्विस गतिविधि सेक्टर में रिक्तियों में 70.7 प्रतिशत गिरावट आई है।

आर्थिक अनुमान समूह, ईवाई आईटीईएम क्लब में मुख्य आर्थिक सलाहकार, हॉवर्ड आर्चर ने कहा, 'ब्रिटिश श्रम बाजार का ताजा आंकड़ा स्पष्ट गिरावट को प्रदर्शित करता है। भुगतान बुरी तरह प्रभावित होने से खरीददारी की क्षमता घट गई है।' लॉकडाउन के कारण लगे विनाशकारी झटके से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के एक कदम के रूप में इंग्लैंड के मुख्य मार्गों पर गैर आवश्यक खुदरा दुकानों को सोमवार से खोलने की अनुमति दे दी। सरकारी खजाने के चांसलर ऋषि सुनक ने कहा, 'अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे और सुरक्षित तरीके से खोलने की हमारी योजना के हिस्से के रूप में सोमवार से किताबें, कपड़े, और इलेक्ट्रॉनिक बेचने वाली दुकानें दो महीने से अधिक समय बाद पहली बार कारोबार के लिए खुल गईं।'

एसबीआई कार्ड ने शुरू की VKYC की सुविधा

आपको ऐसे होगा फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

एसबीआई कार्ड ने अपने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। अब नो योर कस्टमर (KYC) की प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से पूरी हो जाएगी। ग्राहकों के अनुभव को आसान बनाने वाली इस सुविधा को कंपनी ने 'वीकेवाईसी' नाम दिया है। इस संदर्भ में कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह सुविधा एसबीआई कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह कागज रहित, डिजिटल बनाएगी। उल्लेखनीय है कि एसबीआई कार्ड देश की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी है।

कम होगी धोखाधड़ी

कंपनी ने कहा कि वीकेवाईसी से ना सिर्फ धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलेगी। बल्कि यह केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में आने वाली लागत को करीब-करीब आधा कर देगी। कंपनी ने देशव्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 संकट के दौरान आपसी मेलजोल से दूरी के नियमों का पालन करने को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा शुरू की है। एसबीआई कार्ड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरदयाल प्रसाद ने कहा कि हम प्रौद्योगिकी को आगे आकर अपनाने वाली कंपनी हैं। इसके लिए हमने रणनीतिक निवेश किया है और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया है।

क्या है केवाईसी?

दरअसल नो योर कस्टमर (केवाईसी) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित एक पहचान प्रक्रिया है, जिसकी मदद से बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहक के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। केवाईसी का अर्थ होता है ग्राहक को जानिए। बैंक और वित्तीय कंपनियां इसके लिए फॉर्म को भरवा कर इसके साथ कुछ पहचान के प्रमाण भी लेती हैं। इसके लिए पहचान पत्र, पते के प्रमाण, आदि की आवश्यकता होती है।

कोरोना वायरसः अमेरिका ने भारत को 100 वेंटिलेटर की पहली खेप सौंपी

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने में भारत की मदद करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पेशकश के तहत अमेरिका ने भारत को मंगलवार को 100 वेंटिलेंटर सौंपे, जिनकी कीमत करीब 12 लाख डॉलर है। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर ने यहां भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) के मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के महासचिव जनरल आर के जैन को 100 वेंटिलेटरों की पहली खेप सौंपी। अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में बताया कि अमेरिका सरकार ने कोविड-19 से निपटने में भारत की मदद करने के मकसद से अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी (यूएसएआईडी) के जरिए भारत को नए एवं अत्याधुनिक 100 वेंटिलेटरों की पहली खेप दान की राजदूत जस्टर ने कार्यक्रम में कहा, "कोविड-19 वैश्विक महामारी ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य को अप्रत्याशित खतरा पैदा कर दिया है। साझेदारी और सहयोग के जरिए ही हम दुनियाभर के लोगों के लिए स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे."

देश में ई-खुदरा बाजार का कारोबार 2025 तक 120 अरब डॉलर जीएमवी पहुंच जाने का अनुमानः रिपोर्ट

नयी दिल्ली। देश का ई-खुदरा बाजार में तेजी से विकास होगा और 35 करोड़ खरीदारों के साथ इसका कारोबार 2025 तक 100 से 120 अरब डॉलर सकल वस्तु मूल्य (जीएमवी) पर पहुंच जाने का अनुमान है। बेन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि 850 अरब डॉलर मूल्य का भारतीय खुदरा बाजार दुनिया का चौथा बड़ा बाजार है लेकिन इसका बड़ा हिस्सा असंगठित है। इसमें कहा गया है, "यह बाजार ई-खुदरा इकाइयों और भारतीय खरीदारों पर उनके बढ़ते प्रभाव के साथ बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। पिछले पांच साल में देश में ई-खुदरा उद्योग में तीव्र वृद्धि हुई है और आने वाले समय में वृद्धि की काफी गुंजाइश है।" फिलहाल ऑनलाइन खुदरा कारोबार की पहुंच करीब 3.4 प्रतिशत है। सस्ता और दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचता मोबाइल डेटा, ऑनलाइन खर्च का बढ़ता चलन तथा कंपनियों की तरफ से स्थानीय भाषा में उपयोग जैसी सुविधाओं से वित्त वर्ष 2024-25 तक ई-खुदरा बाजार से जुड़े ग्राहकों की संख्या करीब 30 से 35 करोड़ हो जाने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार इससे ऑनलाइन सकल वस्तु मूल्य (जीएमवी) संचयी आधार पर सालाना 30 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा और 2025 तक 100 से 120 अरब डॉलर पुंहच जाने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2019-20 में यह 30 अरब डॉलर जीएमवी था। इसमें फैशन श्रेणी के उत्पाद की महत्वपूर्ण भूमिका होगी जो ऑनलाइन ग्राहकों को आकर्षित करेगा। रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन खरीदारी करने वालें में मझोले और छोटे शहरों का योगदान कुल खरीदारों में करीब आधा होगा और ई-रिटेल मंच पर प्राप्त प्रत्येक पांच आर्डर में तीन आर्डर वहीं से होगा।

भारत ने निकाली चीन के टायरों की हवा इंपोर्ट पर लगाई पाबंदी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत ने चीन के टायरों की हवा निकाल दी है. भारत में इंपोर्ट होने वाले रबर टायरों पर सरकार ने कड़ी पाबंदी लगा दी है। इससे 20 देशों से भारत में आने वाले टायर पर असर पड़ेगा जिनमें थाईलैंड और चाइना से आने वाले टायर भी शामिल हैं। पाबंदी के तहत इंपोर्टर के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, इसके बिना टायर ला नहीं पाएंगे.

इन टायरों पर लगाई पाबंदी

जिन टायरों पर पाबंदी लगी है उनमें मोटरकार, रेसिंग कार, कार, बस, मोटरसाइकिल और साइकिल शामिल है। हालांकि इसमें ट्रक के टायर शामिल नहीं है। टायर मार्केट एक्सपर्ट विपिन कुमार कहते हैं 'चाइना के पास ऐसे कौन से रिसोर्सेस है जो इंडिया के पास नहीं है। हम चाहते हैं कि इंडिया के पास भी वही फैसेलिटीज होनी चाहिए, ताकि प्रोडक्ट तो उनका आए लेकिन बिके नहीं। इतनी कैपेबिलिटी हमारे में होनी चाहिए। यह जो प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है इससे हमारी इंडस्ट्री को टाइम मिलेगा कंपीट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ,चाइना से बेहतर बनाने के लिए। अभी तो यह होता है कोई भी आदमी इंपोर्टर बनता है लाया मार्केट में फेंक दिया, ज्यादा टेंशन नहीं है, पर अब लाइसेंस पॉलिसी लागू हो गई तो रेस्ट्रिक्टेड होगा, कम आना शुरू होगा तो हो सकता है वह भी वही प्राइस पर पहुंचे जहां इंडियन प्राइज है तो ज्यादा बेहतर होगा।

उन्होंने कहा कि चीन से फर्स्ट हैंड टायर आते हैं। चीन अपनी स्पीड से दौड़ेगा वह रुकने वाला नहीं, इतनी बड़ी महामारी में वह नहीं रुका छोटी-मोटी चीजों से वह नहीं रुकेगा। ठीक है इंडिया आज की डेट में सबसे बड़ा मार्केट है, चाइना को इकोनॉमी में झटका तो लगेगा इससे क्योंकि इंडिया बड़ा मार्केट है और वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उपाय निकालेगा, इतना प्रोडक्शन कहां लेकर जाएगा।

क्या चीन समझौते की टेबल पर आएगा?

विपिन कुमार ने कहा कि 'हंड्रेड परसेंट आना चाहिए, जब इकोनॉमी में असर पड़ेगा तो समझौते पर तो आएगा. अभी तो वह ऊपर ही ऊपर घूम रहा है. कहीं तो लाकर बात बातचीत की जा सके तो, एक में डाउन होगा तो करेगा. उसकी सेल कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो चाइना पर बहुत बुरा असर पड़ेगा वह कहां जाएगा ये लेकर. चाइना ने इतनी मार्केट कैप्चर कर ली है कि इंडियन कंपनी के लिए स्पेस कम हो रहा है, लाइसेंस शुरू होने से देसी कंपनियों पर असर पड़ेगा कि उनको टाइम मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव बनने का और प्राइस के लिहाज से या क्वालिटी के लिहाज से वह और बेहतर कर पाएंगे.'

वहीं कारोबारी जसविंदर सिंह कहते हैं कि इंडियन कंपनियों के लिए बहुत अच्छा प्लस पाइंट है कि हमको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमारा माल था। सप्लाई और डिमांड की हम बात करें तो वह मैच नहीं करता था। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था कंजंप्शन कम है। वह इसलिए कम थी क्योंकि चीनी शेयर आ रहा था। अब बेनिफिट मिलेगा सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो मैच होगा।

उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इंडियन कंपनियों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ग्राहकों को भी फायदा होगा क्योंकि इंडियन टायर की क्वालिटी चीन से ज्यादा अच्छी है। चाइना का प्रोडक्ट सस्ता है पर क्वालिटी मैच नहीं करता। इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए बहुत अच्छा है। ग्राहकों के लिहाज से भी अच्छा है। सरकार को थोड़ा बहुत नुकसान है क्योंकि कस्टम ड्यूटी वगैरह मिलती वो नहीं मिलेगी। इससे बड़ा रेवेन्यू आता है, इससे थोड़ा नुकसान होगा लेकिन इंडियन कंपनी को बूस्ट करने के लिए जो सरकार कर रही, वह बहुत अच्छी बात है। इससे मेक इन इंडिया होता है, इकोनॉमी को फायदा होगा। एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि वो चाइनीज कंपनियां जो थाईलैंड या वियतनाम के रास्ते अपने टायर भारत भेजती थीं उनको भी नुकसान होगा।

Defence Canteen से नहीं मिल रहे इन विदेशी शराब कंपनियों को आर्डर 'वोकल फॉर लोकल' पर जोर

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया के दो सबसे बड़े स्प्रिट निर्माताओं में शामिल Pernod Ricard और Diageo ने रक्षा कैंटीन स्टोर्स से अपने आयातित ब्रांडों के लिए आर्डर लेना बंद कर दिया है। कैंटीन में इन्हें रियायती दरों पर बेचा जाता था। रायटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही है। बता दें कि रक्षा कैंटीन में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को स्थानीय और आयातित उत्पादों जैसे शराब और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। एक सूत्र ने कहा कि Pernod Ricard India (जिसके ब्रांडों में Chivas और Glenlivet scotch व्हिस्की शामिल हैं) को आयातित स्प्रिट के लिए मई में कोई आर्डर नहीं मिला, जबकि डिफेंस स्टोर्स की ओर से महीने में 4,500-5,000 गत्ते ऑर्डर दिए जाते हैं। एक गत्ते में आमतौर पर छह, नौ या 12 बोतल शराब होती है। एक दूसरे सूत्र ने कहा कि Diageo India को भी अपने आयातित ब्रांडों के लिए मई के बाद से कोई आर्डर नहीं मिला है, जबकि इस ब्रांड के तहत लोकप्रिय जॉनी वॉकर, ब्लैक लेबल व्हिस्की और टैलिस्कर सिंगल माल्ट आते हैं। इस मामले पर जब Pernod Ricard से पूछा गया तो उसने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि Diageo ने रायटर्स के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं, रक्षा मंत्रालय ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस पर कोई भी लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर बहुत जल्द एक औपचारिक फैसला लिया जाएगा।

कर्ज की स्थगित किस्तों पर ब्याज पर ब्याज वसूलने का कोई तुक नहीं बनता: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोविड- 19 महामारी को देखते हुए घोषित रोक अवधि के दौरान स्थगित कर्ज किस्तों पर ब्याज पर ब्याज वसूलने का कोई तुक नहीं बनता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि एक बार स्थगन तय कर दिए जाने के बाद इसका वांछित उद्देश्य पूरा होना चाहिए। ऐसे में सरकार को सब कुछ बैंकों पर नहीं छोड़कर मामले में खुद हस्तक्षेप करने पर विचार करना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह भी शामिल हैं। पीठ का कहना है, ''जब एक बार स्थगन तय कर दिया गया है तब उसे उसके उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। ऐसे में हमें ब्याज के ऊपर ब्याज वसूले जाने की कोई तुक नजर नहीं आती है।

पीठ ने आगरा निवासी गजेन्द्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा। गजेन्द्र शर्मा ने रिजर्व बैंक की 27 मार्च की अधिसूचना के उस हिस्से को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है जिसमें स्थगन अवधि के दौरान कर्ज राशि पर ब्याज वसूले जाने की बात कही गई है। इससे याचिकाकर्ता जो कि एक कर्जदार भी है का कहना है कि उसके समक्ष कठिनाई पैदा होती है। इससे उसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गये 'जीवन के अधिकार की गारंटी मामले में रुकावट आड़े आती है।

ब्याज को पूरी तरह से माफ करना बैंकों के लिए आसान नहीं

केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से न्यायालय में पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ब्याज को पूरी तरह से माफ करना बैंकों के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि बैंकों को अपने जमाकर्ता ग्राहकों को ब्याज का भुगतान करना होता है। मेहता ने पीठ से कहा, ''बैंकों में 133 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा है जिसपर बैंकों को ब्याज का भुगतान करना होता है। ऐसे में कर्ज भुगतान पर ब्याज माफ करने का इनके कामकाज पर गहरा असर पड़ेगा।

अगली सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में तय करते हुए केन्द्र और रिजर्व बैंक से स्थिति की समीक्षा करने को कहा है, साथ ही भारतीय बैंक संघ से कहा है कि क्या वह इस बीच रिण किस्त भुगतान के स्थगन मामले में कोई नये दिशानिर्देश ला सकते हैं। तुषार मेहता ने कहा रोक अवधि के दौरान कर्ज पर ब्याज भुगतान को पूरी तरह से माफ कर दिए जाने से बैंकों की वित्तीय स्थिरता जोखिम में पड़ सकती है और इससे बैंकों के जमाधारकों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है।

मामले में बैंक संघ और भारतीय स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने पीठ से मामले को तीन माह के लिए आगे बढ़ाने का आग्रह किया। बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने कहा कि रोक अवधि के दौरान ब्याज से छूट दिए जाने संबंधी याचिका असामयिक है और बैंकों को मामला दर माला आधार पर विचार करना होगा। न्यायालय ने इससे पहले 12 जून को वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से तीन दिन के भीतर एक बैठक करने को कहा था जिसमें रोक अवधि के दौरान स्थगित कर्ज किस्त के भुगतान पर ब्याज पर ब्याज वसूली से छूट दिए जाने पर फैसला करने को कहा गया।

शीर्ष अदालत का मानना है कि यह पूरी रोक अवधि के दौरान ब्याज को पूरी तरह से छूट का सवाल नहीं है बल्कि यह मामला बैंकों द्वारा बयाज के ऊपर ब्याज वसूले जाने तक सीमित है। याचिकाकर्ता ने मामले में न्यायालय से सरकार और रिजर्व बैंक को कर्ज भुगतान में राहत दिए जाने का आदेश देने का आग्रह किया है। उसने कहा है कि रोक अवधि के दौरान ब्याज नहीं वसूला जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मामले में 4 जून को वित्त मंत्रालय से रोक अवधि के दौरान कर्ज पर ब्याज से छूट के बारे में जवाब देने को कहा था। इसके बाद रिजर्व बैंक ने कहा था कि ''जबर्दस्ती ब्याज माफी ठीक नहीं होगी। इससे बैंकों की वित्तीय वहनीयता में जोखिम खड़ा हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में दो पहलू विचाराधीन है। पहला रोक अवधि के दौरान कर्ज पर ब्याज का भुगतान नहीं और दूसरा ब्याज के ऊपर कोई ब्याज नहीं वसूला जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण समय है ऐसे में यह गंभीर मुद्दा है कि एक तरफ कर्ज किस्त भुगतान को स्थगित किया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ उस पर ब्याज लिया जा रहा है।

स्थगन अवधि के दौरान बैंक कर्ज पर ब्याज छूट से जमाकर्ताओं के हितों को होगा नुकसान: एआईबीडीए

मुंबई। बैंक जमाकर्ताओं के संगठन 'आल इंडिया बैंक डिपाजिटर्स एसोसियेसन (एआईबीडीए) ने कहा है कि स्थगन अवधि के दौरान बैंक कर्ज पर ब्याज से छूट दिये जाने का जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचेगा। संगठन ने कहा है कि किसी भी तरह की ब्याज छूट दिये जाने से रिण संस्कृति को क्षति पहुंचेगी और साथ ही बैंकों की वित्तीय सेहत पर भी असर पड़ेगा। संगठन ने कहा है कि यदि ब्याज भुगतान में छूट दी जाती है तो इसका जमाकर्ताओं को ''गंभीर खामियाजा'' भुगतना पड़ेगा क्योंकि बैंक ऐसे माहौल में अपनी ब्याज ब्याज आय में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिये जमा की ब्याज दरों में और कटौती करेंगे। जमाकर्ताओं के संगठन ने कहा है कि एतिहासिक रूप से बयाज माफी यदि कोई दी जाती है तो उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन इस समय केन्द्र और राज्यों के स्तर पर सरकारी राजस्व में कमी से इसकी गंजाइश नहीं है।। यहां यह उल्लेखनीय है कि 12 जून को उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और रिजर्व बैंक को तीन दिन के भीतर एक बैठक करने और कोरोना वायरस की वजह से लागू कर्ज वसूली पर स्थगन की अवधि के दौरान कर्ज किस्तों के ब्याज के ऊपर ब्याज से छूट दिये जाने के मुद्दे पर फैसला करने को कहा गया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, एस क कौल और एम आर शाह की पीठ ने कहा, ''हमारा सवाल इसी मुद्दे तक सीमित है क्या ब्याज पर ब्याज से छूट दी जा सकती है।'' पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर संतुलित नजरिया अपनायेगी।

असाधारण है इस बार का सूर्य ग्रहण

5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत के युद्ध का 14वां दिन था, कुरुक्षेत्र के अलावा कई अन्य देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था और दिन में ही अंधेरा छा गया था। वह भारत का महायुद्ध था, आज विश्व पटल पर विश्व युद्ध जैसा वातावरण चल रहा है। क्या 21 जून का सूर्य ग्रहण धरती को कम्पाएगा, धमकाएगा, हिलाएगा, डराएगा या इससे भी कुछ अधिक कर सकता है?

इस बार सूर्य ग्रहण के साथ एक और संयोग है। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना का निर्माण कर रहा है। यह ग्रहण ऐसे दिन होने जा रहा है जब उसकी किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण है जो आषाढ़ महीने की अमावस्या को रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। कंकण आकृति ग्रहण होने के साथ ही यह ग्रहण रविवार को होने से और भी प्रभावी हो गया है। यह बहुत विरल है। जिस तरह का यह ग्रहण है वैसा 900 साल बाद घटित होगा।

21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में लगेगा

एक साथ बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु यह छह ग्रह 21 जून 2020 को वक्री रहेंगे। इन छह ग्रहों का वक्री होना यानी एक बड़ा तहलका मचाने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जा रहा है। हालांकि कंकणाकृति होने का अर्थ यह है कि इससे कोरोना का रोग नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अन्य मामलों में यह ग्रहण अनिष्टकारी प्रतीत हो रहा है।

इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह चंद्र ग्रहण के मात्र 16 दिन बाद लग रहा है। आगामी 5 जुलाई को एक बार फिर से चंद्र ग्रहण लगेगा।

भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण का आरंभ 21 जून की सुबह 10 बजकर 42 मिनट पर होगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण रहेगा। इसका सूतक 20 जून की रात 10 बजे से आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का मध्य 12 बजकर 24 मिनट दोपहर पर होगा। इसका मोक्ष दोपहर 2 बजकर 7 मिनट पर होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 25 मिनट की रहेगी। यह अधिकांश भू-मंडल पर दिखाई देगा।

ग्रहण के दौरान सूर्य वलयाकार की स्थिति में केवल 30 सैकंड की अवधि तक ही रहेगा। इसके चलते सौर वैज्ञानिक इसे विरल बता रहे हैं। ग्रहण के दौरान सूर्य किसी छल्ले की भांति नजर आएगा। इस बार के सूर्य ग्रहण में जो स्थिति बनने जा रही है, उसी ने इसे विरल ग्रहणों में शामिल किया है। सूर्य व चंद्रमा के बीच की दूरी ही इसकी खास वजह है।

ग्रहण के दौरान सूर्य की पृथ्वी से 15 करोड़ 2 लाख 35 हजार 882 कि.मी. की दूरी रह जाएगी। इस दौरान चांद भी 3 लाख 91 हजार 482 कि.मी. की दूरी से अपने पथ से गुजर रहा होगा। अगर चांद इस दौरान पृथ्वी के और पास होता तो यह ग्रहण एक पूर्ण सूर्यग्रहण बन जाता। इसी तरह अगर सूर्य थोड़ा और पास होता तो ग्रहण का नजारा बदल जाता लेकिन अब यह ग्रहण वलयाकार होगा, यानी चांद पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढंक पाएगा। करीब 30 सैकंड के लिए ही चांद सूर्य के बड़े भाग को कवर करेगा। अंत में सूर्य का आखिरी हिस्सा एक चमकती हुई रिंग के समान नजर आएगा। 30 सैकंड के बाद यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा।

राजस्थान में दो जगहों पर सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य का सिर्फ एक प्रतिशत भाग ही दिखाई देगा। इसकी आकृति कंगन जैसी दिखेगी। कंकणाकृति के ग्रहण के समय सूर्य किसी कंगन की भांति नजर आता है। इसलिए इसे कंकणाकृति ग्रहण कहा जाता है। पिछली बार वर्ष 1995 के पूर्ण ग्रहण के समय ऐसा ही हुआ था।

21 जून को सूर्य के वलय पर चंद्रमा का पूरा आकार नजर आएगा। सूर्य का केंद्र का भाग पूरा काला नजर आएगा, जबकि किनारों पर चमक रहेगी। इस तरह के सूर्य ग्रहण को पूरे विश्व में कहीं-कहीं ही देखा जा सकता है और अधिकांश जगह लोगों को आंशिक ग्रहण ही नजर आता है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है, दो चंद्र ग्रहण के साथ होता है। इसमें या तो दोनों चंद्रग्रहण उससे पहले होते हैं अथवा एक चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण से पहले एवं दूसरा सूर्यग्रहण के बाद दिखाई देता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है।

ग्रहण शुभ फल लेकर नहीं आते हैं। ये भविष्य में आने वाली परेशानियों के बारे में भी इंगित करते हैं। देशकाल की बात करें तो एक माह में दो ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं का भी कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त सीमा विवाद, तनाव जैसी स्थिति की तरफ भी इशारा करते हैं। दो ग्रहण कई क्षेत्रों में हानि का सूचक भी होता है। इसलिए इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए।

सूतक का समय

सूतक 20 जून को रात 10.20 से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल में बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर अन्य किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान खाद्य पदार्थों में तुलसी दल या कुशा रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खासतौर से सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल में सोना और भोजन नहीं करना चाहिए। चाकू, छुरी से सब्जी,फल आदि काटना भी निषिद्ध माना गया है।

जरूरतमंद लोगों को करें दान और शुभ काम करने से बचें

✱ सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार सूतक काल में पूजा पाठ और देवी देवताओं की मूर्तियों को भी छूने की मनाही है। इस दौरान कोई शुभ काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता।

✱ सूर्य ग्रहण चूंकि गर्मी के महीने में लग रहा और चंद्रमा अंक 2 का प्रतीक है जो जल, भावना, संवेदना और अवसाद का भी प्रतीक है इन सबको बढ़ाएगा। यह सूर्य ग्रहण निश्चित रूप से जरुरत से ज्यादा पानी लाएगा। भारत में कई जगह बाढ़ की स्थिति बनेगी। प्राकृतिक आपदा में भूकंप आने की भी प्रबल सम्भावना रहेगी। जिस वैश्विक महामारी से समाज गुजर रहा है, इसका कई तरह से प्रभाव आने वाले समय में बना रहेगा। लोगों में आत्म विश्वास की कमी होगी। कुछ देशों में युद्ध की स्थिति बनेगी। अग्नि और जल का असंतुलन होगा।

– मदन गुप्ता सपाटू, ज्योतिर्विद्

हलहारिणी अमावस्या

कालसर्प दोष से परेशान हैं तो हलहारिणी अमावस्या के दिन आजमाएं ये अचूक उपाय

1. हलहारिणी अमावस्या पर सुबह स्नान आदि करने के बाद चांदी से निर्मित नाग-नागिन की पूजा करें और सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कालसर्प दोष से राहत पाने का ये अचूक उपाय है।
2. कालसर्प दोष निवारण के लिए हलहारिणी अमावस्या पर लघु रुद्र का पाठ स्वयं करें या किसी योग्य पंडित से करवाएं। ये पाठ विधि-विधान पूर्वक होना चाहिए।
3. हलहारिणी अमावस्या पर गरीबों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करें व नवनाग स्तोत्र का पाठ करें।
4. हलहारिणी अमावस्या पर सुबह नहाने के बाद समीप स्थित शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर तांबे का नाग चढ़ाएं। इसके बाद वहां बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिवजी से कालसर्प दोष मुक्ति के लिए प्रार्थना करें।
5. हलहारिणी अमावस्या पर सफेद फूल, बताशे, कच्चा दूध, सफेद कपड़ा, चावल व सफेद मिठाई बहते हुए जल में प्रवाहित करें और कालसर्प दोष की शांति के लिए शेषनाग से प्रार्थना करें।
6. हलहारिणी अमावस्या पर शाम को पीपल के वृक्ष की पूजा करें तथा पीपल के नीचे दीपक जलाएं।
7. हलहारिणी अमावस्या पर कालसर्प यंत्र की स्थापना करें-

इसकी विधि इस प्रकार है- सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर का ध्यान करें और फिर कालसर्प दोष यंत्र का भी पूजन करें। सबसे पहले दूध से कालसर्प दोष यंत्र को स्नान करवाएं, इसके बाद गंगाजल से स्नान करवाएं। तत्पश्चात गंध, सफेद पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें। इसके बाद नीचे लिखे मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। कम से कम एक माला जाप अवश्य करें।

मंत्र- अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलम्।
शंखपाल धार्तराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा।।
एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनाम्।
सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः।।
तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्।।

पूजा में गरुड़ घंटी का क्या है राज, नहीं जानते होंगे आप

मंदिर या घर के पूजाघर में आपने देखा होगा गरुड़ घंटी को। मंदिर के द्वार पर और विशेष स्थानों पर घंटी या घंटे लगाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। घंटी विशेष प्रकार का नाद होता है जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है।

यह घंटे या घंटियां 4 प्रकार की होती हैं:- 1.गरूड़ घंटी, 2.द्वार घंटी, 3.हाथ घंटी और 4.घंटा।

1. गरूड़ घंटी : गरूड़ घंटी छोटी-सी होती है जिसे एक हाथ से बजाया जा सकता है।

2. द्वार घंटी : यह द्वार पर लटकी होती है। यह बड़ी और छोटी दोनों ही आकार की होती है।

3. हाथ घंटी : पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है जिसको लकड़ी के एक गद्दे से ठोककर बजाते हैं।

4. घंटा : यह बहुत बड़ा होता है। कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा। इसको बजाने के बाद आवाज कई किलोमीटर तक चली जाती है।

गरुड़ : भगवान गरुड़ को विष्णु का वाहन और द्वारपाल माना जाता है। अधिकतर मंदिरों में मंदिर के बाहर आपको द्वार पर गरुड़ भगवान की मूर्ति मिलेगी। दक्षिण भारत के मंदिरों में अक्सर इसे देखा जा सकता है।

आखिर यह घंटा या घंटा क्यों रखा जाता है। क्या कारण है इसका जानिए

इस संबंध में 5 रहस्य।

1. हिंदू धर्म सृष्टि की रचना में ध्वनि का महत्वपूर्ण योगदान मानता है। ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति और बिंदु रूप प्रकाश से ध्वनि की उत्पत्ति का सिद्धांत हिंदू धर्म का ही है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद था, घंटी की ध्वनि को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। यही नाद ओंकार के उच्चारण से भी जाग्रत होता है।

2. जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती है। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वारा खुलते हैं। प्रातः और संध्या को ही घंटी बजाने का नियम है। वह भी लयपूर्ण।

3. घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब भी इसी प्रकार का नाद यानि आवाज प्रकट होगी।

4. जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती है। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वारा खुलते हैं।

5. स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से मानव के सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है।

कोरोना काल के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 50 हजार करोड़ डॉलर हो जाना सुखद आश्चर्य

नयी दिल्ली। एजेंसी

इन दिनों देश अभूतपूर्व आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है। अर्थव्यवस्था की गाड़ी डगमगा गई है। मगर एक सुखद पहलू यह है कि कोरोना की बड़ी मार के बाद भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। देश में चौतरफा निराशाजनक स्थिति है और उदासीनता के परिवेश से सभी जकड़े हुए हैं। बावजूद इसके विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 50 हजार करोड़ डॉलर हो जाना एक सुखद आश्चर्य ही कहा जाएगा। फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार की बढ़त के बीच भारत का बचा हुआ विकास दर यदि शीघ्र पटरी पर नहीं आता है तो बढ़त ले चुकी आर्थिक चुनौतियां देश में नाउम्मीदी का माहौल बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगी। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का एक फायदा यह होता है कि इससे सरकार और आरबीआइ को देश के बाह्य और आंतरिक आर्थिक मामलों को सुलझाने में कहीं अधिक मदद मिलती है। गौरतलब है कि मई में विदेशी मुद्रा भंडार में 1,240 करोड़ डॉलर का उछाल आया और माह के अंत तक यह लगभग 50 हजार करोड़ डॉलर के पास पहुंच गया। रुपये में इसे लगभग 37 लाख करोड़ से अधिक कह सकते हैं। वैसे कई लोग सोचते होंगे कि जब देश की माली हालत सबसे बड़े आर्थिक गिरावट में है, उद्योग-धंधे तथा सेवा क्षेत्र समेत छोटे-बड़े कारोबार कोरोना की चपेट में हैं तो ऐसे में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ रहा है।

जाहिर है इसका कोई आर्थिक कारण तो होगा। वैसे विदेशी मुद्रा भंडारण की बढ़त में भारत ही नहीं, बल्कि चीन भी इस मामले में सुखद स्थिति में है। गौरतलब है कि मई में चीन के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े से पता चलता है कि माह के अंत तक यहां यह भंडार 31 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया जो अप्रैल की तुलना में 0.3 फीसद बढ़त लिए हुए है। हालांकि इन दिनों चीन कोरोना से राहत में है और भारत कोरोना के बीच उलझा हुआ है। ऐसे में भले ही चीन बढ़त में हो, पर भारत में मिल रही बढ़त उसकी बेहतरी का सूचक है। विदेशी मुद्रा भंडार आगामी एक वर्ष के आयात बिल के लिए शुभ संकेत दे रहा है। साथ ही इसकी बढ़त से यह भी संकेत मिलता है कि डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत होगा और भुगतान संतुलन के मामले में सकारात्मकता आएगी। भारत की जीडीपी भारत के विकास का जरिया है और यहां की कुल जीडीपी में 15 प्रतिशत विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। इस मामले में यदि संतुलन बरकरार रहता है तो 15 फीसद वाला हिस्सा मजबूत रहेगा, लेकिन बाकी के 85 फीसद के लिए सरकार को एड़ी-चोटी का जोर लगाना ही होगा। विदेशी मुद्रा भंडार की बढ़त सभी समस्याओं का हल नहीं है लेकिन बढ़त ले चुकी समस्याओं का आनुपातिक हल जरूर है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का प्रमुख कारण भारतीय शेयरों में विदेशी निवेश, साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जा रहा है। गौरतलब है कि विदेशी निवेशकों द्वारा अप्रैल और मई माह में कई भारतीय कंपनियों में रकम लगाई गई जो इसकी बढ़त का एक बड़ा कारण है। साथ ही भारतीय कंपनियों पर इस कदम से विश्वास भी बढ़ता दिखाई देता है।

विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत पांचवें स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर।कोरोना संकट से उपजी समस्या के चलते कई यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियां चीन से विस्थापित होने का मन बना चुकी हैं और प्राथमिकता में भारत को भी देखा जा सकता है। ऐसे में भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए। अमेरिका 19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ पहले तो चीन 13 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत लगभग तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है जो 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर के मसौदे पर आगे बढ़ रहा था, मगर गत एक तिमाही में सारे प्रयासों पर पानी फिर गया है। हालांकि कोरोना महामारी से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त थी। मूडीज की रिपोर्ट ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2 फीसद कर दिया है।

इतना ही नहीं, विकास दर को मौजूदा स्थिति के अंतर्गत ऋणात्मक होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। हालांकि मूडीज की रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2 फीसद होगी। यह तो आने वाला समय बताएगा पर आरबीआइ का संदर्भ भी विकास दर के मामले में कहीं अधिक गिरावट से युक्त देखा जा सकता है।

कोरोना का मीटर इन दिनों भारत में तेजी लिए हुए है और लॉकडाउन को लगभग समाप्त कर अनलॉक को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार उखड़ती अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा मरहम है। विदेशी मुद्रा भंडार सोना और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर समेत विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों हेतु भारत द्वारा संचित एवं आरबीआइ द्वारा नियंत्रित की जाने वाली बाहरी संपत्ति है।

गौरतलब है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में अधिकांश हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा संपत्तियों की ही है। जब संकट का समय आता है और उधार लेने की क्षमता घटने लगती है तो विदेशी मुद्रा आर्थिक तरलता को बनाए रखने में मददगार होती है। ऐसे में भुगतान संतुलन से लेकर कई आर्थिक संतुलन डगमगाने से पहले संभल जाते हैं।

संक्रमण काल में चीनी मिलों को सलाह

शक्कर के बजाय बनाएं हल्दी व तुलसी वाला गुड़

नई दिल्ली। एजेंसी

एनएसआइ के वेबिनार में इंटरनेशनल शुगर ऑर्गनाइजेशन के अर्थशास्त्री ने किया आह्वान शामिल हुए कई देशों के प्रतिनिधी हुए। इसमें बताया गया कि यह अवसर चीनी मिलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मिलें चीनी उत्पादन के बजाय हल्दी, दालचीनी, अदरक, तुलसी वाला गुड़ या गन्ने के रस में इनको मिलाकर हेल्थ ड्रिंक्स तैयार करें तो ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। यह आह्वान इंटरनेशनल शुगर ऑर्गनाइजेशन के अर्थशास्त्री पीटर डी क्लार्क ने किया। वह मंगलवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) की शर्करा बाजार एवं शर्करा खपत विषय पर आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे। वेबिनार में श्रीलंका, केन्या, इटली, सिंगापुर, ब्राजील, इंडोनेशिया के प्रतिनिधि शामिल हुए।

मधुमेह, दंत रोग के लिए चीनी ही दोषी नहीं

इस दौरान निदेशक प्रो.नरेंद्र मोहन ने कहा कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गनाइजेशन ने 100 से अधिक देशों में शर्करा से जुड़ी भ्रांतियों पर सर्वेक्षण किया है। केवल चीनी ही मधुमेह, दंतरोग, मोटापे की वजह नहीं है। यह अनियमित जीवनशैली, व्यायाम से दूरी, कैलोरीयुक्त और असंतुलित भोजन के कारण हो सकता है।

लैंड में चीनी उत्पादन की कमी का लाभ उठा सकता भारत

इंटरनेशनल शुगर ऑर्गनाइजेशन के अर्थशास्त्री पीटर डी क्लार्क ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सामाजिक कार्यक्रम कम हुए, जिससे मिठाई, आइसक्रीम, पेय पदार्थों की खपत कम रही। इसका असर चीनी पर भी पड़ा। चीनी उत्पादन और कीमतों में कमी आई है। इसकी खपत को लेकर भी अनिश्चितता बनी है। ऐसे में एशिया में थाईलैंड की उत्पादकता में 40 फीसद गिरावट का लाभ भारत उठा सकता है। मिस्र, सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत एशिया के अन्य आयातक देशों को चीनी निर्यात की जा सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण ब्राजील भी इस वर्ष गन्ने से इथेनॉल के बजाय चीनी उत्पादन करने की तैयारी में है।

ईपीएएफओ ने पीएफ खाताधारकों को दी एक और बड़ी राहत

किसी भी कार्यालय में होगा पीएफ दावों का निपटारा

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में कोरोना संकट के इस दौर में नौकरीपेशा करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने पीएफ खातो से भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी के साथ दावों और हस्तांतरित दावों की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया है। मलसन अब ईपीएफओ के अंशधारकों के सभी प्रकार के दावों का निपटान किसी भी नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से किया जा सकता है। वहीं कर्मचारियों को पीएफ खातों से पैसा निकालने में भी आसानी होगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों के दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए देशभर में यह नई सुविधा शुरू की है। मंत्रालय के अनुसार देशभर में ईपीएफओ द्वारा अपनी सेवा वितरण के समान मानकों को सुनिश्चित करने, खासतौर से कोरोना महामारी के दौरान अपने कार्यबल का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस दिशा में ईपीएफओ ने देशभर में किसी भी ईपीएफओ कार्यालय यानि विभिन्न स्थानों से अपने अंशधारकों के दावों के निपटान की सुविधा को शुरू की है। इस नई सेवा के तहत देशभर में ईपीएफओ कार्यालयों या किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों का निपटारा करने की अनुमति दी गई है। मसलन इस पहल के जरिए सभी प्रकार के ऑनलाइन दावों यानी भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और हस्तांतरित दावों की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

मंत्रालय के अनुसार ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालय

ईपीएफओ के देशभर में 135 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण मुंबई, ठाणे, हरियाणा और चेन्नई क्षेत्र में कई कार्यालय सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं, जबकि अन्य कार्याल्य 50 फीसद कार्यबल के साथ काम कर रहे हैं। यही कारण है कि ईपीएफओ में दावों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। इन लंबित दावों के निपटान और अंशधारकों को राहत देने की दिशा में ईपीएफओ ने लंबित दावों के काम को सभी कार्यालयों को बराबर संख्या में वितरित करके शीघ्र निपटारा करने का फैसला किया है। हालांकि हाल ही में शुरू किए गए ऑटो सेटलमेंट मोड की मदद से कोरोना संबन्धी दावों के निपटान की अवधि को कम करके 3 दिनों तक किया जा रहा है। ईपीएफओ की इस पहल से विभिन्न स्थानों से दावा निपटान सुविधा के द्वारा दावा प्रक्रिया के लिए भौगोलिक क्षेत्राधिकार की मौजूदा प्रणाली से बाहर निकल गया है। यह कदम पूरे देश में ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यबल के सबसे सटीक जुड़ाव के माध्यम से दावा निपटान प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करने में सक्षम साबित होगा।

गुरुग्राम के दावे का पंजाब में समाधान

मंत्रालय के अनुसार ईपीएफओ ने अपने अंशधाराकों की समस्या के समाधान को सरल एवं सुगम बनाने के मकसद से इस पहल में अनुभव किया है। मसलन इस अग्रणी परियोजना के अंतर्गत बहु-स्थानीय दावों का पहला बैच 10 जून को गुरुग्राम क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया। इसके तहत गुरुग्राम क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित कर्मचारियों के दावों का निपटारा चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर कार्यालयों में तैनात ईपीएफओ के कर्मचारियों द्वारा किया गया। दावों के निपटान के बाद गुरुग्राम कार्यालय से पीएफ खाताधारकों के व्यक्तिगत बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित की गई है। इसी अनुभव के आधार पर ईपीएफओ ने देशभर में इस प्रक्रिया को अपनाते हुए सभी क्षेत्रीय कार्यालयो में दावों के निपटान की अनुमति दी है। इसकी शुरूआत के बाद से, नियंत्रित क्षेत्रों में आने वाले कार्यालयों से संबंधित दावों को त्वरित प्रक्रिया के लिए अन्य स्थानों के कार्यालयों में वितरित किया जा रहा है।

80 हजार से ज्यादा दावों को निपटान

ईपीएफओ के अधिकारी और कर्मचारी अपने समर्पण और निरंतर नई पद्धतियों के माध्यम से कोरोना महामारी प्रतिबंधों के कारण अपने कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बावजूद 1 अप्रैल 2020 से प्रति कार्य दिवस में 270 करोड़ रुपये की राशि के 80 हजार से ज्यादा दावों का निपटान किया है। विभिन्न स्थानों से दावा निपटान सुविधा के साथ संकट के दौरान ईपीएफओ अपने 6 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेवा वितरण में उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए तैयार है।

हेल्थ इंश्योरेंस का है कवर, तब भी कोविड-19 के इलाज में निकल रही है जमा-पूंजी

नई दिल्ली। एजेंसी

कहते हैं कि आपने ठीक-ठाक रकम की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो फिर आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन, कोरोना वायरस से फैली बीमारी कोविड-19 ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है। इस समय हालत यह है कि जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस हैं, उनकी भी कोविड-19 के इलाज में जमा-पूंजी निकल रही है।

पूरा भुगतान नहीं कर रही हैं बीमा कंपनियां

जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) द्वारा आवधिक रूप से संकलित किए गए उद्योग के आंकड़ों (यह आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जाते) से पता चलता है कि इस क्षेत्र की स्थिति सामान्य नहीं है। इन आंकड़ों के मुताबिक इस समय कोरोना पेशेंट के अस्पताल में भर्ती होने का जो औसत बिल आ रहा है वह 1.56 लाख रुपए का है। लेकिन इनमें से इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा 90,118 रुपये का ही सेटलमेंट किया जा रहा है।

क्या है सेटलमेंट अमाउंट

हेल्थ इंश्योरेंस का कवर प्राप्त कोई भी व्यक्ति यदि किसी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होता है तो उनके इलाज में जो भी खर्च का बिल आता है वह क्लेम अमाउंट (Claim amount) कहलाता है। इस राशि में से बीमा कंपनी जिस रकम का भुगतान करती हैं वह सेटलमेंट अमाउंट (settlement amount) कहलाता है। सेटलमेंट अमाउंट और क्लेम के बीच की राशि को तकनीकी भाषा में out-of-pocket

एक्सपेंस कहा जाता है, जो कि मरीज या उसका परिवार उठाता है।

कोविड-19 के इलाज में ज्यादा नहीं हो रहा है सेटलमेंट

जानकारी के अनुसार बीते 9 जून तक कोविड-19 के 11405 मामले सेटलमेंट के लिए बीमा कंपनियों के पास आए। इन मामलों में करीब 178 करोड रुपए का क्लेम था। इनमें से 6,495 क्लेम के मामले को निपटाए गए और बीमा कंपनियों ने 58 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,361 क्लेम सामने आए जिनमें से 3,099 क्लेम का भुगतान किया गया। दिल्ली में 1,919 क्लेम आए जिनमें से 1,407 क्लेम सेटल हुए।

एक नई चुनौती का सामना

क्षेत्र के जानकारों का कहना है की कोरोना मरीजों के इलाज में एक अजीब तरह की चुनौती सामने आ रही है। कोविड-19 के अधिकतर मामलों में ट्रीटमेंट कॉस्ट में ओवरहेड कंज्यूमेबल की भी कीमत जुड़ी हुई है। इस तरह की लागत बीमा कंपनियां आमतौर पर कवर नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में कोरोना मरीज का एवरेज क्लेम साइज 2,29,000 रुपये का है और इनमें से उन्हें आधा से भी कम मतलब 1,04,000 रुपये का ही सेटलमेंट मिला है। महाराष्ट्र में देखें तो ओवरहेड कंज्यूमेबल का हिस्सा कम है वहां एवरेज क्लेम साइज 1,19,000 रुपये का है जबकि बीमा कंपनियों ने औसतन 82,000 रुपये का भुगतान किया है। पश्चिम बंगाल में भी कमोबेश स्थिति दिल्ली जैसे ही हैं जहां एवरेज क्लेम साइज 2,51,000 करोड़ रुपये का है। उनमें से बीमा कंपनियों ने 1,14,000 रुपये का भुगतान किया है। हरियाणा में एवरेज क्लेम साइज 1,56,000 रुपये का है जबकि बीमा कंपनियों ने 84,000 रुपये का भुगतान किया है। कर्नाटक में एवरेज क्लेम साइज 2,09,000 रुपये का है जबकि बीमा कंपनियों ने 1,09,000 रुपये का भुगतान किया है।

भारत 2019 में नौवां सबसे अधिक एफडीआई पाने वाला देश

लगातार निवेश आकर्षित करता रहेगा: संरा रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र। एजेंसी

भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डालर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और वह वर्ष के दौरान दुनियाभर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पाने वाले देशों में नौवें नंबर पर रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोविड- 19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापक बाजार देश के लिये निवेश आकर्षित करते रहेंगे। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि भारत 2019 में 51 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने साथ वर्ष के दौरान दुनियाभर में नौवें नंबर पर रहा। इससे पिछले वर्ष 2018 में भारत को 42 अरब डालर का एफडीआई प्राप्त हुआ था। तब भारत एफडीआई पाने वाले शीर्ष 20 देशों में 12वें नंबर पर रहा था। विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनियाभर में प्रतयक्ष विदेशी निवेश में 40 प्रतिशत तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। यह गिरावट 2019 में हुये 1,540 अरब डालर के प्रवाह के मुकाबले आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह 2005 के बाद पहला अवसर होगा कि दुनिया के देशों में एफडीआई पहली बार एक हजार अरब डालर के आंकड़े से नीचे आ जायेगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते एशिया के विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह 2020 में 45 प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया गया है। दक्षिण एशिया के देशों में भी एफडीआई में 2020 के दौरान गिरावट आने का अनुमान है।

हरियाणा ने कपड़े, उर्वरक, जूते-चप्पल पर जीएसटी दरें घटाने की मांग की

चंडीगढ़। एजेंसी

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद से वस्त्र, उर्वरक और जूते-चप्पल पर कर की दरें कम करने की मांग की। चौटाला ने जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक के दौरान पांच करोड़ रुपये से कम जीएसटी भरने वाले लोगों के लिये भी कर जमा करने की समयसीमा बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों में राज्य के समक्ष उपस्थित हो रहे जीएसटी से संबंधित कई अन्य मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद चौटाला ने कहा कि हरियाणा ने केंद्र सरकार से वस्त्र, उर्वरक और जूते-चप्पल पर कर की दरें कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गुजरात और बिहार ने भी इसी तरह की मांग की। चौटाला ने कहा कि उन्होंने उन लोगों पर जुर्माना हटाने की मांग की, जो पिछले तीन वर्षों में रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्रीय राजस्व बढ़ाने के लिये इस दंड को समाप्त किया जाना चाहिये। चौटाला ने बैठक में कहा कि पांच करोड़ से कम जीएसटी का भुगतान करने वालों के लिये कर जमा करने की समय सीमा जून से आगे सितंबर 2020 तक बढ़ाई जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को संकट की इस घड़ी में वित्तीय सहायता के रूप में राज्यों को उपकर राशि देनी चाहिये। उन्होंने बताया कि 2017 में, इस श्रेणी में 1.76 लाख करोड़ रुपये एकत्र किये गये। इनमें से 34 हजार करोड़ रुपये राज्यों को वितरित किये गये, लेकिन 54,600 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार के पास लंबित है।

अप्रैल-मई में रत्न, आभूषण निर्यात 82.31 प्रतिशत घटकर 4,328.54 करोड़ रुपये पर

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश का रत्न एवं आभूषण निर्यात चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-मई माह के दौरान 82.31 प्रतिशत घटकर 4,328.54 करोड़ रुपये पर आ गया। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोविड-19 महामारी फैलने की वजह से दुनियाभर में लॉकडाउन के चलते रत्न एवं आभूषण निर्यात में भारी गिरावट आई है। अप्रैल-मई, 2019 के दौरान रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 24,468.11 करोड़ रुपये रहा था। जीजेईपीसी के वाइस चेयरमैन कोलिन शाह ने कहा, "वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन की वजह से निर्यात प्रभावित हुआ है। अब चीन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में मांग कुछ सुधर रही है।" शाह ने कहा कि खाड़ी के ज्यादातर देशों और अमेरिका में अभी इस महामारी का प्रभाव कायम है। उद्योग की

स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, लेकिन निश्चित रूप से हम सभी सुरक्षा नियमों का अनुपालन कर रहे हैं।

इस बीच, आंकड़ों के अनुसार कट और पालिश किए गए हीरों का निर्यात अप्रैल-मई में 77.42 प्रतिशत घटकर 2,943.18 करोड़ रुपये पर आ गया, जो इससे पिछले साल के समान महीनों में 13,033.41 करोड़ रुपये रहा था। इसी तरह सोने के आभूषणों का निर्यात 92 प्रतिशत की भारी गिरावटके साथ 7,927.47 करोड़ रुपये से 634.38 करोड़ रुपये पर आ गया। रंगीन रत्नों का निर्यात 92.90 प्रतिशत घटकर 28.98 करोड़ रुपये रह गया, जो इससे पिछले साल की समान अवधि में 408.45 करोड़ रुपये था। हालांकि, इस दौरान चांदी के आभूषणों का निर्यात 5.46 प्रतिशत बढ़कर 647.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो अप्रैल-मई, 2019 में 614.21 करोड़ रुपये रहा था।

डनलप बना रही एन-95 मास्क : रुइया

कोलकाता। एजेंसी

डनलप ब्रांड नाम से गद्दों का कारोबार करने वाले रुइया समूह ने कहा कि उसने एन95 मास्क का विनिर्माण शुरू किया है। इसी के साथ कंपनी ने स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरण बनाने के क्षेत्र में प्रवेश किया है। कंपनी को उम्मीद है कि कोविद-19 महामारी के चलते अगले दो साल में इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये का बाजार बनेगा।रुइया समूह के चेयरमैन पवन रुइया ने कहा कि उन्होंने डनलप ब्रांड नाम के एन95 मास्क का वितरण शुरू किया है। यह अभी पूर्वी भारत के बाजारों में उपलब्ध है। जल्द ही इसे पूरे भारत में बेचा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जतायी की डनलप के ब्रांड नाम की वजह से बाजार में इस उत्पाद को अच्छी पकड़ मिलेगी।डनलप ब्रांड टायर के लिए भी मशहूर है।रुइया ने कहा कि मास्क सिर्फ शुरुआत है। कंपनी जल्द ही पीपीई किट को भी उतारेगी। कंपनी का लक्ष्य हर माह एक लाख एन95 मास्क, दो लाख सर्जिकल मास्क और 10,000 पीपीई के उत्पादन का है।

चीन की एंटीबैक्टीरिया दवा पर भारत लगा सकता है एंटी-डंपिंग शुल्क

नयी दिल्ली। एजेंसी

सस्ते आयात से घरेलू उद्योग को बचाने के लिए भारत चीन की एंटीबैक्टीरिया दवा सिप्रोफ्लोक्सासिन डाइहाइड्रोक्लोराइड पर एंडी-डंपिंग शुल्क लगा सकता है। आरती ड्रग्स लिमिटेड ने चीन से दवा के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की याचिका दायर की थी। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपाय महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने अपनी शुरुआती जांच के तहत चीन के उत्पाद पर अस्थाई रूप से एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की। इस सिफारिश के तहत 0.94 डॉलर प्रति किलोग्राम से 3.29 डॉलर प्रति किलोग्राम तक शुल्क लगाने की बात कही गई है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।